RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 05 AUGUST TO 11 AUGUST 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 50 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

कोयला खदान नीलामी में चीनी कंपनियों को NO एंट्री Page 2

कारोबार में लाइसेंस राज खत्म करने की मांग, फैम ने पीएम मोदी को लिखा पत्र Page 3

भारतीय बैंकों के लिए 20-ट्रिलियन का छेद Page 4

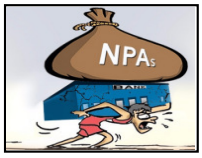

editoria!

कोरोनाः कैसे बचे इकॉनमी

कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ी विश्वव्यापी जंग का सबसे गंभीर पहलू अब सामने आ रहा है। बीते सप्ताह जारी हुए जीडीपी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून तिमाही में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले फ्रांस ने 13.8 फीसदी, जर्मनी ने 10.1 फीसदी, स्पेन ने 18.5 फीसदी और इटली ने 12.4 फीसदी की गिरावट दर्ज की। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका ने इस तिमाही में पिछले साल के मुकाबले 9.5 फीसदी की गिरावट देखी। यह भीषण गिरावट साफ इशारा कर रही है कि सिर्फ ये गिनी-चुनी अर्थव्यवस्थाएं ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में पड़ गई है। लॉकडाउन भले इस संकट की शुरुआत का कारण बना हो, पर इसका उठाया जाना संकट का अंत नहीं साबित हो रहा। विभिन्न देशों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बावजूद जिंदगी की पुरानी रौनक कहीं भी वापस नहीं लौटी है। ऐसे में आर्थिक गतिविधियों का जाम हो चुका चक्का भी पुरानी रफ्तार नहीं हासिल कर पा रहा है, हालांकि इसके लिए कोशिशें पूरी की जा रही हैं। मई से ही की जा रही आर्थिक पैकेजों की घोषणा इन कोशिशों की धुरी है। यूरोपियन यूनियन ने अभी हाल में 750 अरब यूरो (878 अरब डॉलर) का रिकवरी फंड बनाने का फैसला किया है। इसका कैसा उपयोग होता है और आर्थिक हलचलों पर इसका क्या असर होता है, यह देखना होगा। लेकिन अमेरिका में इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ है। वहां 3 लाख करोड़ डॉलर का आर्थिक पैकेज दिया जा चुका है, जिसका एक हिस्सा कंपनियों के खाते में इस मकसद से गया कि वे कर्मचारियों की छंटनी न करें तो दूसरा हिस्सा दसियों लाख बेरोजगारों को हर हफ्ते 600 डॉलर की सहायता देने में खर्च किया गया। अब यह प्रक्रिया समाप्ति पर पहुंच रही है तो वहां दूसरे पैकेज की मांग तेज हो गई है, हालांकि जीडीपी के आंकड़े वहां अपनी ही कहानी कह रहे हैं। इस संदर्भ में भारत का अनुभव भी ज्यादा अलग नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित किया गया 20 लाख करोड़ का विशाल पैकेज कहां खर्च हुआ और उसका कितना फायदा हुआ, इसका हिसाब अभी आना बाकी है। यहां भी पिछले हफ्ते सीआईआई की बैठक में उद्योग जगत की ओर से लोन रीस्ट्रक्चर किए जाने की मांग मजबूती से उठाई जा चुकी है। पैकेज का ठोस और पॉजिटिव असर अगर कहीं दिखता है तो चीन में, जहां मई महीने में अपेक्षाकृत छोटा पैकेज (जीडीपी का महज 4.6 फीसदी) घोषित किया गया। दिलचस्प है कि चीनी अर्थव्यवस्था ने पिछली तिमाही में क्लासिक वी शेप्ड रिकवरी की तरह नीचे से सीधे ऊपर जाने का रुझान दर्ज कराया। इस महत्वपूर्ण फर्क का सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन ने कोरोना पर काबू पा लेने के बाद यह पैकेज घोषित किया, जिससे वहां आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ सकीं। लेकिन भारत और अमेरिका में वायरस से लड़ाई अभी खात्मे की ओर जाती नहीं दिख रही, लिहाजा हमें आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल सोच-समझकर करते हुए आगे बढ़ना होगा।

आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से कदम

जुलाई में निर्यात पिछले साल के स्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। देश के निर्यात में उल्लेखनीय सुधार दिख रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि जुलाई में निर्यात पिछले साल के समान महीने के स्तर के करीब रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कई संकेतक हैं जिनसे पता चलता है कि देश में आर्थिक गतिविधियों की स्थिति सुधर रही है।

जुलाई 2019 के 90 फीसदी तक निर्यात पहुंचा

गोयल ने कहा, 'हमारा निर्यात पिछले साल के जुलाई के स्तर पर पहुंच गया है। जुलाई, 2019 का करीब 90 प्रतिशत निर्यात का आंकड़ा हमने पा लिया है। वास्तव में हम इसमें तेल से संबंधित निर्यात हटा दें, जिसका मूल्य से हिसाब से हिस्सा काफी कम होता है, तो जुलाई में हमारा निर्यात पिछले साल के समान महीने के 95 प्रतिशत से अधिक रहा है।'

आत्मनिर्भर भारत पर जोर

मंत्री ने कहा, 'आज देश का 'मूड' सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने का ही नहीं है, बल्कि आज हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हम अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं और उनकी कीमतों को प्रतिस्पर्धी करना चाहते हैं।' वाणिज्य मंत्रालय जुलाई के निर्यात के आधिकारिक आंकड़े अगस्त मध्य में जारी करेगा। जून में लगातार चौथे महीने देश के निर्यात में गिरावट आई थी।

जून में 18 सालों में पहली बार ट्रेड सरप्लस था

इस दौरान आयात में अधिक बड़ी 47.59 प्रतिशत की गिरावट की वजह से देश 18 साल में पहली बार ट्रेड सरप्लस की स्थिति में पहुंचा था। कोविड-19 की वजह से कमजोर वैश्विक मांग से जून में मूल्य के हिसाब से देश का निर्यात 12.41 प्रतिशत घटकर 21.91 अरब डॉलर रहा था। अप्रैल में निर्यात 60.28 प्रतिशत घटा था। मई में इसमें 36.7 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

भारत में 21 यूनिकार्न स्टार्टअप

कुल मूल्यांकन 73 अरब डालर, चीन के दसवें हिस्से के बराबरः अध्ययन

मुंबई। एजेंसी

भारत में यूनिकॉर्न स्तर के स्टार्टअप की संख्या करीब 21 है। एक अरब डॉलर से अधिक मूल्य वाले इन स्टार्टअप की संख्या पड़ोसी देश चीन के मुकाबले दसवें हिस्से के बराबर है। भारतीय निवेशकों की 40 से अधिक ऐसी कंपनियां विदेशों में स्थापित हैं। हुरुन की वैश्विक यूनिकॉर्न सूची में 21 भारतीय यूनिकॉर्न कंपनियों का कुल मूल्यांकन 73.2 अरब डॉलर है। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के बाद भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है। यूनिकॉर्न ऐसी स्टार्टअप कंपनियों को कहा जाता है जिनका मूल्यांकन एक अरब डॉलर या उससे अधिक होता है। हुरुन की रपट के अनुसार चीन में यूनिकॉर्न की संख्या 227 है। ऐसे में भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या उसके दसवें हिस्से के बराबर है। इतना ही नहीं भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश को विभिन्न नियमों के दायरे में लाये जाने की खबरों के बीच यह बात उल्लेखनीय है कि घरेलू 21 यूनिकॉर्न में से 11 में चीन के तीन निवेशकों का बड़ा हिस्सा है। भारत से बाहर भारतीय मूल के लोगों द्वारा स्थापित यूनिकॉर्न की संख्या करीब 40 है जबकि चीनी मूल के लोगों ने अपने देश से बाहर मात्र 16 ऐसे कारोबार स्थापित किए हैं। भारतीय समुदाय द्वारा विदेशों में स्थापित यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन 99.6 अरब डॉलर है। इसमें सबसे अधिक मूल्यांकन वित्त प्रौद्योगिकी कंपनी रॉबिनहुड का करीब 8.5 अरब डॉलर है। हुरुन रपट के चेयरमैन और मुख्य अनुसंधानकर्ता रुपर्ट हूगवर्फ ने कहा कि भारतीयों द्वारा स्थापित 61 यूनिकॉर्न में से करीब दो-तिहाई विदेशों में मुख्य तौर पर अमेरिका के सिलिकॉन वैली में है। मात्र 21 यूनिकॉर्न ही देश में काम कर रही हैं। रपट में कहा गया है कि

दुनिया के 29 देशों के 145 शहरों में 586 यूनिकॉन कंपनियां काम करती हैं। भारत में काम कर रही 21 यूनिकॉर्न कंपनियों में से अधिकतर ई-वाणिज्य क्षेत्र की हैं और बेंगलुरू भारत की यूनिकॉर्न राजधानी कही जा सकती है क्योंकि इनमें से आठ कंपनियां बेंगलुरू में स्थित हैं। देश की सबसे नयी यूनिकॉर्न कंपनियों में ओला इलेक्ट्रिक, उड़ान और स्विगी हैं। रपट के मुताबिक भारत में किसी स्टार्टअप को यूनिकॉन के स्तर पर पहुंचने में करीब सात साल का वक्त लगता है, जबकि चीन में यह वक्त साढ़े पांच साल और अमेरिका में साढ़े छह साल है।

लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को मिली ई-पॉलिसी करने की अनुमति, जानिए क्या है नियम

नई दिल्ली। एजेंसी

मुख्य बातेंकोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैंसामान्य कारोबारी एक्टिविटी में प्रभावित हो रही हैंईईईई ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस पॉलिसी की अनुमति दे दी है कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना जरूरी है। इसलिए अधिकांश लोग घर नहीं निकल रहे हैं। इससे सामान्य कारोबारी एक्टिविटी में प्रभावित हो रही हैं। इन परेशानियों को देखते हुए इंश्योरेंस रेगुलेटर ईईईई ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी यानी ई-पॉलिसी जारी करने की अनुमति दे दी।

नियम से छूट

इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डवलपमेंट ऑथरिटी ऑफ इंडिया (ईईईई) ने एक सर्कुलर जारी कर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी दस्तावेज को प्रकाशित कर बीमाधारक के पास भेजने के नियम से छूट प्रदान कर दी। हालांकि, यह छूट सशर्त दी गई है। इरडा ने कहा कि यह छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए मान्य रहेगी। विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों के ग्राहकों तक पॉलिसी भेजने में आ रही दिक्कतों को लेकर चिंता व्यक्त करने के बाद ईईईई ने यह फैसला किया है।

ई-पॉलिसी के नियम

लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को ई-पॉलिसी को देखने-समझने के लिए ग्राहक को 30 दिन का समय देना होगा। साथ ही ग्राहकों से ई-पॉलिसी लेने को लेकर सहमति हासिल करनी होगी। यदि ग्राहक उसके बाद भी हार्ड कॉपी या दस्तावेज की मांग करता है तो कंपनियों को उसे वह भेजना होगा। इस बीच रेगुलेटर ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को प्रत्येक तिमाही उनकी निवेश रिटर्न इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजने की भी अनुमति दे दी है।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने की नई योजना को गडकरी ने दी मंजूरी, सरकार दे रही है मदद, शुरू करें बिजनेस

नई दिल्ली। एजेंसी

देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (ख्ब्ष्) आगे आया है। केंद्रीय श्एर्ई मंत्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (ख्ब्ष्) द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। 'खादी अगरबत्ती आत्म-निर्भर मिशन' नाम के इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना और घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में पर्याप्त तेजी लाना है। इस प्रस्ताव को पिछले महीने मंजूरी के लिए श्एर्ई मंत्रालय के समक्ष रखा गया था। प्रायोगिक परियोजना जल्द ही शुरू की जाएगी। इस परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन होने पर अगरबत्ती उद्योग में हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर का सृजन होगा।

प्राइवेट सार्वजनिक मोड पर ख्ब्ष् द्वारा बनाई गई यह योजना इस मायने में अद्वितीय है कि बहुत कम निवेश में ही यह स्थाई रोजगार का सृजन करेगा और प्राइवेट अगरबत्ती निर्माताओं को उनके बिना किसी पूंजी निवेश के अगरबत्ती का उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। इस योजना के तहत, ख्ब्ष् सफल प्राइवेट अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से कारीगरों को अगरबत्ती बनाने की स्वचालित मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराएगा जो व्यापार भागीदारों के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ख्ब्ष् ने केवल स्थानीय रूप से भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्मित मशीनों की खरीद का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना भी है।

KVIC मशीनों की लागत पर 25% सब्सिडी प्रदान करेगा और कारीगरों से हर महीने आसान किस्तों में शेष 75% की वसूली करेगा। व्यापार भागीदार कारीगरों को अगरबत्ती बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएगा और उन्हें काम के आधार पर मजदूरी का भुगतान करेगा। कारीगरों के प्रशिक्षण की लागत KVIC और निजी व्यापार भागीदार के बीच साझा की जाएगी, जिसमें KVIC लागत का 75% वहन करेगा, जबकि 25% व्यापार भागीदार द्वारा भुगतान किया जाएगा।

अगरबत्ती बनाने की प्रत्येक स्वचालित मशीन प्रति दिन करीब 80 किलोग्राम अगरबत्ती बनाती है जिससे 4 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। अगरबत्ती बनाने की 05 मशीनों के सेट पर एक पाउडर मिक्सिंग मशीन दी जाएगी, जिससे 2 लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी अगरबत्ती बनाने की मजदूरी 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। इस दर से एक स्वचालित अगरबत्ती मशीन पर काम करने वाले 4 कारीगर 80 किलोग्राम अगरबत्ती बनाकर प्रतिदिन न्यूनतम 1200 रुपए कमाएंगे। इसलिए प्रत्येक कारीगर प्रति दिन कम से कम 300 रुपए कमाएगा। इसी तरह पाउडर मिक्सिंग मशीन पर प्रत्येक कारीगर को प्रति दिन 250 रुपए की निश्चित राशि मिलेगी।

योजना के अनुसार, व्यापार भागीदारों द्वारा साप्ताहिक आधार पर कारीगरों को मजदूरी सीधे उनके खातों में केवल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। कारीगरों को कच्चे माल की आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स, गुणवत्ता नियंत्रण और अंतिम उत्पाद का विपणन करना केवल व्यापार भागीदार की जिम्मेदारी होगी। मशीन की शेष 75% लागत की वसूली के बाद इसका मालिकाना हक स्वतः कारीगरों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

इस संबंध में पीपीपी मोड पर परियोजना के सफल संचालन के लिए ख्ब्ष् और निजी अगरबत्ती निर्माता के बीच दो-पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस योजना को दो प्रमुख फैसलों, अगरबत्ती के कच्चे माल पर आयात प्रतिबंध और बांस के डंडों पर आयात शुल्क में बढ़ो?तरी, को देखते हुए बनाया गया। ये फैसले नितिन गडकरी की पहल पर क्रमशः वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए।

KVIC के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि केंद्र सरकार के दो फैसलों ने अगरबत्ती उद्योग में रोजगार के बड़े अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन के बड़े अवसर को भुनाने के लिए KVIC ने 'खादी अगरबत्ती आत्म-निर्भर मिशन' नामक एक कार्यक्रम तैयार किया और मंजूरी के लिए श्एर्ई मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कारीगरों का साथ देना और स्थानीय अगरबत्ती उद्योग की मदद करना है। देश में अगरबत्ती की वर्तमान खपत लगभग 1490 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। हालांकि, भारत में अगरबत्ती का उत्पादन प्रतिदिन केवल 760 मीट्रिक टन ही है। मांग और आपूर्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए, इसमें रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं।

भारत में ईंधन की मांग सामान्य स्तर तक पहुंचने में 6-9 महीने लग सकते हैं: आईओसी

नयी दिल्ली। एजेंसी

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के वित्त निदेशक एस के गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि भारत में ईंधन की मांग सामान्य स्तर तक पहुंचने में छह से नौ महीने का समय लग सकता है, क्योंकि कई राज्यों में कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में पेट्रोल-डीजल की मांग में 45.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी। लॉकडाउन के प्रतिबंधों में मई की शुरुआत से क्रमिक रूप से ढ़ील दी गई, लेकिन कई राज्य दैनिक संक्रमण को कम करने के लिए अभी भी लॉकडाउन लागू कर रहे हैं। गुप्ता ने पहली तिमाही के नतीजों पर चर्चा के लिए आयोजित एक निवेशक बैठक में कहा कि भारत और दुनिया भर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुधार के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है। उन्होंने कहा, ''इसे सामान्य होने में छह से नौ महीने लग सकते हैं।'' मई में ईंधन की मांग में तेजी आने के बाद जून से ईंधन की मांग फिर घटने लगी। गुप्ता ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में 26,233 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की योजना है। इसमें लगभग 4,200 करोड़ रुपये रिफाइनरी उन्नयन और पाइपलाइन पर खर्च करने की योजना है। इसके अलावा 5,000 रुपये मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर, 2200 करोड़ रुपये पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं पर और 5,000 करोड़ रुपये समूह कंपनियों पर खर्च करने की योजना है। उन्होंने कहा, ''हम इस पूंजीगत व्यय को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि पहले से मंजूर पूंजीगत व्यय को टालने का कोई अर्थ नहीं। हम चाहते हैं कि सभी योजनाओं (अनुमोदित) को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।''

भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते की बेहतर परिणाम के लिये तत्काल समीक्षा की जरूरत: पुरी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि भारत-आसियान के बीच वस्तु व्यापार पर हुये समझौते की तत्काल समीक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे भारत तथा दस दक्षिणपूर्वी एशियाई देशों के इस समूह के बीच द्विपक्षीय व्यापार की वास्तविक संभावनाओं का पता चल सकेगा। भारत-आसियान के बीच वस्तुओं के व्यापार पर हुये समझौते की समीक्षा लंबित है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजि एक आभासी सम्मेलन में कहा, ''समझौते की तत्काल समीक्षा और आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के प्रभावी कार्यान्वयन से दोनों पक्षों द्वारा 2020 के लिए निर्धारित 200 अरब अमरीकी डालर के व्यापार लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।'' पुरी ने कहा कि एफटीए की समीक्षा से भागीदार देशों को उपलब्ध संभावनाओं को साकार करने के अवसर मिलेंगे। सरकार ने पिछले साल नवंबर में संसद को बताया था कि भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की समीक्षा के प्रस्तावित दायरे में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, वस्तुओं के व्यापार आगे और उदारीकरण तथा आंकड़ों के आदान-प्रदान जैसे मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। दस देशों के समूह आसियान और भारत के बीच वस्तु व्यापार समझौते पर 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर हुए और यह एक जनवरी 2010 को लागू हुआ। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के संघ (आसियान) के सदस्यों में इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमा, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि भारत और आसियान दोनों को ही ई- वाणिज्य, आईटी संबद्ध सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग और पर्यटन जैसे सेवा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में दोगुने प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आसियान के साथ भारत का सालाना व्यापार घाटा 24 अरब डालर के करीब है। ''इसके कई कारण हैं और मैं चाहता हूं कि आने वाले महीनों और सालों में यह घाटा कम होना चाहिये। ''

कोयला खदान नीलामी में चीनी कंपनियों को NO एंट्री

भारत ने उठाया सख्त कदम

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों को वाणिज्यिक दोहन के लिए कोयला खदान की जारी नीलामी में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए जारी टेंडर दस्तावेज के लिए एक शुद्धिपत्र जारी किया है और इस तथ्य को सामने लाया है कि यद्यपि ऑटोमेटिक रूट के तहत नई गतिविधि में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है, लेकिन भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश प्रस्तावों को केवल सरकार के रूट से ही स्वीकृत किया जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी भागीदारी की अनुमति से पहले ऐसे प्रस्तावों को सरकार जांचेगी-परखेगी। उन कंपनियों के प्रस्तावों को भी सरकार के रूट से गुजरना होगा, जिनके मालिक भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले किसी देश में रहते हैं या वहां के नागरिक हैं। टेंडर दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान का कोई नागरिक या पाकिस्तान में निगमीकृत कोई संस्था सिर्फ सरकार के रूट से गुजरने के बाद ही रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा को छोड़कर और विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित सेक्टर को छोड़कर बाकी सेक्टर में निवेश कर सकती है। कोयला मंत्रालय ने स्पष्टीकरण इसलिए जारी किया है, ताकि निवेशक बोली से पहले अपनी पात्रता के बारे में जान लें। सरकार ने पूर्व में जारी 2020 के प्रेस नोट 3 के जरिए भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से सभी निवेश के लिए सरकारी रूट से मंजूरी के तहत कर दिया था। यह कदम भारत के महत्वपूर्ण और संवेदनशील सेक्टरों में चीनी कंपनियों के फैलाव को रोकने के लिए था। बाद में लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष ने एक आधार तैयार किया, जहां आधिकारिक एजेंसियां पड़ोसी देश से निवेश और आयात रोकने के अतिरिक्त उपायों पर विचार कर रही हैं। प्रथम चरण की वाणिज्यिक कोयला नीलामी के तहत कुल 17 अरब टन के कोयला भंडार वाली 41 खदानें पेश की गई हैं। इसमें विशाल और छोटी खदानें दोनों शामिल हैं। ये खदानें पांच राज्यों में स्थित हैं। ये राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा हैं।

कारोबार में लाइसेंस राज खत्म करने की मांग, फैम ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में व्यापारियों की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया व्यापार मंडल (फैम) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यापारियों की कारोबारी सुगमता के लिए नगर निगमों द्वारा व्यापार पर विभिन्न ट्रेड लाइसेंस को समाप्त कर केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली बनाने का आग्रह किया है। फैम ने निराशा व्यक्त करते हुई लिखा है कि व्यापारी समुदाय खासकर बड़े शहरों के दुकानदारों को अभी कारोबारी सुगमता का लाभ नहीं मिल पा रहा है और व्यापारियों को केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के अतिरिक्त स्थानीय निकायों (विशेषकर नगर निगम) एवं पुलिस प्रशासन के विभिन्न प्रकार के लाइसेंस को प्राप्त करना अनिवार्य है।

इन अनेकों लाइसेंस लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि एक व्यापारी को सलाहकारों के माध्यम से ही ये लाइसेंस प्राप्त हो सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में एक व्यापारी को औसतन औसतन पचास हज़ार से एक लाख रुपये तक प्रति वर्ष तक खर्च करने पड़ जाते हैं जिसमें सरकार को प्राप्त होने वाली कर की धनराशि बहुत कम होती है।

कैसे मिलता है ट्रेड लाइसेंस

फैम का कहना है कि ट्रेड लाइसेंस विभिन्न नगर निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। एक छोटी से छोटी दुकान खोलने के लिए किसी भी व्यापारी को नगर निगम से एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। जिस व्यापारी के पास पहले से ही कंपनी कानून या पार्टनरशिप कानून के तहत पंजीकरण है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आयकर का पैन कार्ड है, फूड सेफ्टी का लाइसेंस है, स्थानीय निकाय द्वारा जारी हेल्थ लाइसेंस (खाद्य वस्तु के दूकानदार के लिए) शॉप एक्ट का पंजीकरण है, बैंकों से ऋण प्राप्त किया हुआ है, बिजली/ टेलीफोन के कनेक्शन है, उसे भी नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है।

इस मद से इन स्थानीय निकायों को कोई भारी आय नहीं होती, परन्तु एक व्यापारी के लिए यह एक उत्पीड़न भरा कार्य है और इसमें भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर होता है। नगर निगम/नगर पालिकाओं द्वारा व्यावसायिक भवन या दुकानों पर संपत्ति कर वसूला जाता है जो रिहायशी क्षेत्र के मुकाबले लगभग 15 गुना ज्यादा होता है। जब एक व्यापारी या दुकानदार व्यावसायिक संपत्ति पर एक बढ़ा हुआ संपत्ति कर देता है तो ऐसे अवस्था में ट्रेड लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

राष्ट्रीय व्यापार नीति बने

फैम ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरह राष्ट्रीय व्यापार नीति बनाई जाए और व्यापारियों के लिए उद्योग आधार की भांति एक केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली को प्रारम्भ किया जाए। केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली के तदुपरांत व्यापारी/दुकानदार को किसी अन्य किसी सरकारी तंत्र से किसी अन्य लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त हो जाए।

फैम के राष्ट्रीय महामंत्री वी के बंसल ने कहा कि केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली से दूसरा लाभ यह होगा कि इससे न केवल एक पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी बल्कि सरकार के पास राष्ट्र के समस्त व्यापारियों का एक परिष्कृत आंकड़ा भी उपलब्ध होगा और सरकार को व्यापारियों के हितो में कोई भी योजना बनाने में सुविधा होगी। केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली व्यवस्था आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक मील का पत्थर साबित होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यह स्थानीय बाज़ारों को विकसित करने में भी सहायक सिद्ध होगी और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का आधार बनेगी।

रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने तथा उद्योग जगत की ऋण पुनर्गठन की बढ़ती मांग के बीच द्वैमासिक मौद्रिक नीति पर मंगलवार को तीन दिवसीय चर्चा शुरू कर दी। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति छह अगस्त को बैठक के नतीजों की घोषणा करने वाली है। यह एमपीसी की 24वीं बैठक है। रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी तथा इसकी रोकथाम के लिये लागू लॉकडाउन के असर को सीमित करने के लिये पिछले कुछ समय से लगातार सक्रियता से कदम उठा रहा है। तेजी से बदलती वृहद आर्थिक परिस्थिति तथा वृद्धि के बिगड़ते परिदृश्य के कारण रिजर्व बैंक की दर निर्धारण समिति को पहले मार्च में और फिर मई में समय से पहले ही बैठक करने की जरूरत पड़ी थी। मार्च और मई 2020 के अंत में हुई बैठकों में रेपो दर में कुल 1.15 प्रतिशत की कटौती की जा चुकी है। इससे पहले फरवरी 2019 से अब तक रेपो दर में 2.50 प्रतिशत तक कटौती की जा चुकी है। हालांकि, विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर एकराय नहीं है कि समिति इस सप्ताह की बैठक में नीतिगत दर में कटौती करेगी या नहीं। कई विशेषज्ञों की राय है कि मौजूदा स्थिति में कर्ज का एक बार पुनर्गठन अधिक आवश्यक है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक शोध रिपोर्ट इकोरैप में कहा गया कि बैंकों ने भी नये कर्ज पर 0.72 प्रतिशत तक ब्याज को सस्ता किया है। कुछ बड़े बैंकों ने तो 0.85 प्रतिशत तक का लाभ ग्राहकों को दिया है। यह संभवतः भारतीय इतिहास में सबसे तेजी से राहत दिये जाने का मामला है। एसबीआई ने रेपो से जुड़े कर्ज की ब्याज दरों को 1.15 प्रतिशत सस्ता किया है। उल्लेखनीय है कि मांस, मछली, खाद्यान्न और दालों की अधिक कीमतों के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जून में 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गयी। हालांकि, रिजर्व बैंक को सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत (दो प्रतिशत ऊपर या नीचे) के दायरे में रखने का लक्ष्य दिया है। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति निर्धारित करते समय मुख्य रूप से सीपीआई पर गौर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एमपीसी तेजी से बदलते व्यापक आर्थिक माहौल के मद्देनजर मौद्रिक नीति पर उदार रुख बरकरार रखेगी।

आकलन वर्ष 2018- 19 में आयकर रिटर्न की जांच का आंकड़ा घटकर 0.25 प्रतिशत पर आया

नयी दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्रालय का कहना है कि जांच पड़ताल के लिये उठाई जाने वाली आयकर रिटर्न (आईटीआर) का आंकड़ा 2018- 19 में कुल दायर आयकर रिटर्न के मुकाबले घटकर 0.25 प्रतिशत रह गया। इससे पहले 2017- 18 में यह अनुपात 0.55 प्रतिशत था। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार रात जारी ट्वीट में कहा, "आयकर विभाग अब केवल आयकर कानून का प्रवर्तन करने वाली इकाई से आगे बढ़कर कर भुगतान सेवाओं को बेहतर बनाने वाले विभाग के तौर पर अपने में बदलाव ला रहा है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुये पिछले कुछ सालों के दौरान जांच के लिये चुनी जाने वाली आयकर रिटर्न की संख्या में भारी कमी आई है।" मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आकलन वर्ष 2015- 16 में जांच के लिये चुनी गई कुल रिटर्न की संख्या 0.71 प्रतिशत थी जो कि 2016- 17 में कम होकर 0.40 प्रतिशत, 2017- 18 में 0.55 प्रतिशत और 2018- 19 में 0.25 प्रतिशत रह गई। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों में दाखिल आयकर रिटर्न की संख्या और कुल दाखिल रिटर्न में से जांच के लिये चुनी गई आईटीआर का प्रतिशत दिया गया है। इसके मुताबिक आकलन वर्ष 2018- 19 में दाखिल कुल रिटर्न की संख्या 2017- 18 के मुकाबले बढ़ी है। इन आंकड़ों के मुताबिक ओडिशा में आकलन वर्ष 2018- 19 के दौरान जांच के लिये उठाये गये मामलों की संख्या घटकर 0.12 प्रतिशत रह गई जो कि एक साल पहले 0.37 प्रतिशत पर थी। पंजाब में यह इस अवधि में 0.40 प्रतिशत से घटकर 2018- 19 में 0.14 प्रतिशत रह गई। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक ओडिशा में 2018- 19 में 10.29 लाख आईटीआर दाखिल किये गये जबकि 2017- 18 में इनकी संख्या 8.31 लाख रही थी। वहीं पंजाब में इस अवधि में क्रमशः 27.65 लाख और 23.44 लाख रिटर्न दाखिल की गई। पश्चिम बंगाल में आकलन वर्ष 2018- 19 में 38.93 लाख आईटीआर दाखिल किये गये जबकि इससे पिछले वर्ष इस राज्य से 33.64 लाख आईटीआर दाखिल किये गये थे।

ये रिपोर्ट कहती है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बुरे दिन लगता है बीत चुके

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है और आर्थिक गतिविधियों को क्रमबद्ध तरीके से अनुमति दी जा रही है। ऐसे में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) की मासिक आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगता है अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा वक्त बीत चुका है, क्योंकि प्रमुख संकेतकों में सुधार दिख रहा है। मंगलवार को जारी जुलाई की रिपोर्ट में कहा गया है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स (पीएमआई), विद्युत उत्पादन, इस्पात और सीमेंट उत्पादन, रेलवे माल ढुलाई, प्रमुख बंदरगाहों पर यातायात, ई-वे बिल जनरेशन के अलावा अन्य संकेतक दिखाते हैं कि आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ ली हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत में अनलॉकिंग के साथ लगता है सबसे बुरा वक्त समाप्त हो गया, क्योंकि उच्च तीव्रता वाले संकेतक अप्रैल 2020 में बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में सुधार दिखाते हैं।" रिपोर्ट में हालांकि कहा गया है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों और राज्यों में बीच-बीच में हो रहे लॉकडाउन के कारण जोखिम की स्थिति बनी हुई है। इसमें कहा गया है कि वृद्धि में तेजी आने वाले महीनों में ग्रामीण भारत से मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य मॉनसून के अनुमान के आधार पर कृषि क्षेत्र वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामारी के असर को कम करने में मददगार साबित हो सकता है।

निवेशकों ने एक दिन में कमाए दो लाख करोड़ रुपये

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि समय पर और सक्रियता के साथ इस सेक्टर के लिए लॉकडाउन में छूट देने से रबी फसलों की मड़ाई सुगमता से हो पाई और खरीब की बुवाई भी बढ़ी है। इसमें कहा गया है, "गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी से किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में निजी उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। सितंबर, 2019 से व्यापार की शर्तें कृषि क्षेत्र के पक्ष में मुड़ी हैं और ग्रामीण मांग बढ़ी है।"

भारतीय बैंकों के लिए 20-ट्रिलियन का छेद

देश में बनते बिगडते आर्थिक हालात

नई दिल्ली। एजेंसी

कई केंद्रीय बैंक गवर्नरों के विपरीत, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर, शक्तिकांत दास जिन्होंने महामारी के दौरान सख्त रहने की भरसक कोशिश की है, पिछले सप्ताह के अंत में एक बैंकिंग कॉन्क्लेव में, उन्होंने कहाः 'महामारी का आर्थिक प्रभाव ... उच्च गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) और बैंकों के पूंजी क्षरण का परिणाम हो सकता है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (इएँ) और निजी बैंकों के लिए पुनर्पूंजीकरण योजना आवश्यक हो गई है।'

सरल शब्दों में, दास ने जो कहा वह यह था कि कोविद -19 के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव से उधारकर्ताओं द्वारा बढ़ती चूक बढ़ेगी। कितना बुरा होने वाला है? यदि 31 अगस्त तक ऋणों का एक-तिहाई हिस्सा जो एक अधिस्थगन के तहत होने की संभावना है, पर चूक हो जाती है, तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बुरे ऋणों की कुल मात्रा 12 ट्रिलियन के करीब होगी। यदि उनमें से पांचवां हिस्सा एक बार स्थगन हटा लिया जाता है, तो बुरे ऋणों की मात्रा एक चक्कर ओर 20 ट्रिलियन को छू लेगी, जो वर्तमान स्तर से दोगुना है।

ये निश्चित रूप से अत्यंत रूढ़िवादी अनुमान हैं। आश्चर्य नहीं कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने हाल ही में कहाः 'एनपीए का स्तर अब से छह महीने अभूतपूर्व होगा।' बढ़ी हुई चूक के साथ, बैंकों को पुनर्पूंजीकरण करने की आवश्यकता होगी, अर्थात उन्हें चालू रखने के लिए अधिक धन का निवेश करना होगा। वास्तव में, आने वाले दिनों में और आसन्न तूफान के पहले से ही बैंकिंग प्रणाली में बढ़ते दबाव के पर्याप्त सबूत हैं।

छेद का आकार

रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुसार, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रबंधन के तहत 52% संपत्ति मई 2020 तक रोक दी गई थी। भले ही इन ऋणों में से 10% पर चूक हो गई हो, एनबीएफसी की सकल एनपीए से अधिक होगी मार्च 2021 तक 6.2% तक पहुंचें। वे मार्च 2020 तक 4.6% पर थे। सकल एनपीए, जिन्हें बुरा ऋण भी कहा जाता है, मूल रूप से ऋण हैं जो 90 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए चुकाए नहीं गए हैं।

एनबीएफसी के स्तर पर कोई भी परेशानी बैंकों पर फैलने की संभावना है। पोस्ट डिमैनेटाइजेशन के बाद, बैंकों के पास जमा के रूप में आने वाला एक पैसा था, जिसने शेडो बैंकिंग क्षेत्र में अपना रास्ता खोज लिया। दिसंबर 2016 तक, एनबीएफसी को बैंक ऋण 3.22 ट्रिलियन था। मई 2020 तक, उधार 8.04 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। इसलिए, यदि एनबीएफसी उधारकर्ताओं का डिफ़ॉल्ट है, तो एनबीएफसी को बैंक ऋण चुकाने में मुश्किल होगी।

जुलाई की शुरुआत में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि रेटिंग फर्मों ने RBI को एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है जहां उन्होंने सुझाव दिया है कि उन्हें कई कंपनियों के क्रेडिट स्कोर प्रकाशित करने से रोकना होगा जो पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं कर रहे हैं या शुल्क का भुगतान करना बंद कर दिया है। रेटिंग फर्मों के लिए यह संभावित रूप से लगभग आधी कंपनियों को प्रभावित कर सकता है जो वर्तमान में एक नियमित रेटिंग अभ्यास से गुजरती हैं। इसलिए, कई कंपनियां परेशानी में हैं और जानकारी साझा न करके इसे छिपाना चाहती हैं। जाहिर है, आने वाले महीनों में, इनमें से कई कंपनियां अपने ऋणों को चुकाने की स्थिति में नहीं रहेंगी।

हालिया रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल से लेकर जून के बीच 5.58 मिलियन वेतनभोगी व्यक्तियों ने अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते से पैसे निकाले, जिससे आय में गिरावट का संकेत मिला। इसलिए, कई व्यक्ति अब उन ऋणों को चुकाने की स्थिति में नहीं हैं जो उन्होंने बैंकों और एनबीएफसी से लिए थे। केवल यही कारण है कि वे डिफ़ॉल्ट रूप से शुरू नहीं करते हैं क्योंकि 31 अगस्त तक वे अपने ऋणों के लिए स्थगन का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन चूक सितंबर के बाद से फट जाएगी।

सामान्य तौर पर, निजी बैंकों ने लगभग सभी नई भर्ती को रोक दिया है। लेकिन वे अपने ऋण-वसूली कार्यों में लोगों को भर्ती करना जारी रखते हैं। यह इस तथ्य का एक स्पष्ट संकेत है कि वे बढ़े हुए खुदरा ऋण चूक को संभालने के लिए कमर कस रहे हैं। असुरक्षित ऋण देने वाले मोर्चे पर परेशानी अधिक होगी, अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत ऋण, उपभोक्ता टिकाऊ ऋण और क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि जैसे ऋण।

समयरेखा

यह देखते हुए कि मार्च के अंत में लॉकडाउन शुरू हो गया था, खराब ऋणों को पहले ही अब तक जमा होना शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए, बैंक 31 अगस्त के 90 दिन बाद, यानी 1 दिसंबर के बाद से ऋणों को ऋण के रूप में वर्गीकृत करना शुरू कर देंगे।

3 जून की रिपोर्ट में, मैक्वेरी सिक्योरिटीज के सुरेश गणपति, पार्थ गुटखा और निशांत शाह का अनुमान है कि 'वर्तमान में ऋण पुस्तिका का 20-30ज्ञ अधिस्थगन के तहत है। ... बैंकों और परामर्शों की प्रतिक्रिया के आधार पर प्रारंभिक संकेत यह है कि अगस्त के अंत तक, ऋण पुस्तिका का 50ज्ञ से अधिक अधिस्थगन के तहत हो सकता है। '

30 जून की एक अन्य रिपोर्ट में, काजल गांधी, विशाल नारनोलिया और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के यश बत्रा लिखते हैंः '(क) अधिस्थगन प्रवृत्ति के संदर्भ में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अधिस्थगन के लिए लगभग 40-50% पुस्तक की सूचना दी। मिड-साइज़ प्राइवेट बैंक एमएसएमई, ऑटो और एमएफआई सेगमेंट के लिए पर्याप्त जोखिम के कारण 50% से ऊपर

उच्च अधिस्थगन की सूचना दी, जो सबसे अधिक प्रभावित थे। इसके विपरीत, बड़े आकार के निजी बैंकों की अधिस्थगन पुस्तक लगभग 20-30% कम थी। ' इसलिए, यह मानना सुरक्षित है कि 31 अगस्त तक लगभग आधे बैंक ऋण एक अधिस्थगन के तहत होंगे। 19 जून तक, वाणिज्यिक बैंकों का कुल गैर-खाद्य ऋण 101.56 ट्रिलियन था।

भारतीय खाद्य निगम राज्य खरीद एजेंसियों के साथ मिलकर किसानों से सीधे तौर पर कृषि फसलें, मुख्य रूप से चावल और गेहूं खरीदता है। बैंक इस खरीद को वित्त करते हैं। एक बार इन ऋणों को बैंकों द्वारा दिए गए समग्र ऋणों से घटा दिया जाता है जो कि गैर-खाद्य ऋण है। पिछले कुछ महीनों में क्रेडिट में धीमी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, बता दें कि 31 अगस्त तक गैर-खाद्य ऋण लगभग 102 ट्रिलियन तक बढ़ जाता है। यदि इनमें से आधे ऋण एक अधिस्थगन के तहत जाते हैं, तो यह लगभग 51 ट्रिलियन के ऋण के बराबर होगा। यहां तक कि अगर केवल 5% ऋण जो कि अधिस्थगन के तहत होने की उम्मीद है, उस पर डिफ़ॉल्ट हैं, तो हम 2.55 ट्रिलियन के अतिरिक्त बुरे ऋण देख रहे हैं। 5% और 10% डिफ़ॉल्ट दरों पर, अतिरिक्त खराब ऋण क्रमशः 5.1 ट्रिलियन और 7.65 ट्रिलियन की राशि होगी। 20% डिफ़ॉल्ट दर पर, हम 20 10.2 ट्रिलियन के अतिरिक्त बुरे ऋण देख रहे हैं।

यहां यह कहने की जरूरत है कि ऋण को स्थगन के तहत रखने के लिए लागत के साथ आता है। एक अधिस्थगन के तहत अवधि के लिए ऋण पर देय ब्याज को मूल बकाया में जोड़ा जाएगा और एक उधारकर्ता को एक उच्च राशि चुकानी होगी। साथ ही, यहां यह कहने की जरूरत है कि ज्यादातर बैंकों ने कर्जदारों को अधिस्थगन के लिए ऑप्ट-इन करने का विकल्प दिया। इसलिए, केवल उधारकर्ताओं को जो वास्तव में पैसे के लिए बढ़ाया जाएगा, ने अधिस्थगन के लिए चुना होगा। इसे देखते हुए, संभावना है कि उनमें से एक अच्छी संख्या डिफ़ॉल्ट होगी। जैसा कि मैक्वेरी के विश्लेषकों ने पहले बताया थाः 'अगर हम ऋण पुस्तिका के 20% ऋण को खराब मानकर चल रहे हैं, तो गैर-निष्पादित ऋण (एनपीएल) अभिवृद्धि 10% पर होगी जिसका अर्थ है कि एनपीएल 10% के वर्तमान स्तर से दोगुना होगा।

बचाव की योजना

यहां यह बताने की जरूरत है कि बैंक पिछले एक दशक में खराब ऋणों की भारी समस्या से जूझ रहे हैं। 31 मार्च 2018 तक, भारतीय बैंकों का बुरा ऋण 6 10.36 ट्रिलियन पर पहुंच गया था। रिकवरी और राइट-ऑफ के लिए 31 मार्च 2020 तक खराब ऋण 9.4 ट्रिलियन (आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अनुसार) की राशि थी। खराब ऋण दर 9.4% थी। इसलिए, यदि अधिस्थगन के तहत होने वाले ऋण के 20ज्ञ पर चूक हुई है, तो बुरे ऋणों में एक और 10.2 ट्रिलियन जोड़ा जाएगा। इसलिए कुल बैड लोन 20 ट्रिलियन या 20% बैंकिंग लोन के करीब होगा। भले ही एक अधिस्थगन के तहत होने वाले ऋणों के केवल 5% पर चूक हुई हो, हम कुल मिलाकर लगभग 12 खरब के बुरे ऋण और 12% की खराब ऋण दर को देख रहे हैं।

एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के अनंत नारायण ने जून की शुरुआत में लिखा था,'' अभी थोड़ी देर के लिए, आरबीआई ने बैंकों को 8 ट्रिलियन से अधिक की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति मान्यता स्थगित करने की अनुमति दी है MSME, MUDRA और वाणिज्यिक अचल संपत्ति ऋण। 'यदि हम इसे ध्यान में रखते हैं, तो समग्र चित्र और भी डरावना हो जाता है।

ऐसी दुनिया में जहां बुरे ऋणों की वसूली की दर अधिक थी, यह एक बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूली की दर पिछले वर्षों में गिर गई है। 2012-13 में, विभिन्न तंत्रों के माध्यम से वसूली जाने वाली राशि का लगभग 22% वसूला गया था। 2018-19 तक, यह गिरकर 15.5% हो गया था। और यह इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड तस्वीर में आने के बावजूद है।

इस गंभीर परिदृश्य को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि RBI गवर्नर दास पहले से ही बैंकों के पुनर्पूंजीकरण योजना के बारे में बात कर रहे हैं। यह शायद ही आश्चर्य की बात है कि सबसे बड़े निजी बैंक पहले से ही उस समय के लिए तैयार होने के लिए अधिक पूंजी जुटाने की प्रक्रिया में हैं, जब ऋण की चूक शुरू हो जाती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में 15 जुलाई के अनुमान में कहा गया है, 'अगले 12-18 महीनों में बैंकों द्वारा इक्विटी बढ़ाने के लिए यूएस $ 20 बिलियन,(1.5 ट्रिलियन) से अधिक ...' इसका मतलब यह भी है कि वित्तीय सेवाओं के विभाग में नौकरशाह, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जिम्मेदार हैं, को इन बैंकों के लिए अधिक पूंजी जुटाने की संभावना के लिए जागना होगा। परेशानी यह है कि अगर सरकार इन बैंकों में अपने स्वामित्व के स्तर को बनाए रखना चाहती है, तो इसके लिए उन्हें और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। और अभी, यह पैसे की बहुत कमी है।

अक्टूबर 2017 से, सरकार ने पुनर्पूंजीकरण बांड जारी करके इस समस्या के आसपास अपना काम किया है। सरकार बॉन्ड जारी करती है जिसे PSB द्वारा खरीदा जाता है। सरकार तब इस धन का उपयोग पीएसबी में निवेश करने के लिए करती है और उन्हें पूंजी प्रदान करती है। मूल रूप से, यह है कि सरकार बैंकों से पैसा उधार लेती है और इसे पूंजी में परिवर्तित करती है।

यह मूल रूप से एक लेखांकन चाल के अलावा कुछ भी नहीं है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकार पीएसबी में करों के माध्यम से अर्जित धन को समाप्त नहीं करती है। अक्टूबर 2017 से, ाह 2.5 ट्रिलियन से अधिक मूल्य के बांड जारी किए गए हैं।

आगे का रास्ता

यह समय ऐसा है जब सरकार को पीएसबी में अपनी हिस्सेदारी को 33% तक बढ़ाने का विचार आया, कुछ ऐसा जो तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने फरवरी 2000 में किए गए बजट भाषण में किया था। इससे पीएसबी को अपनी पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। वित्तीय बाजार। बेशक, यह सब तभी होगा जब दिन की सरकार ऐसा करना चाहेगी। निष्कर्ष निकालने के लिए, यदि पिछले दशक का अनुभव कुछ भी हो जाए, तो क्या होने की संभावना है कि सड़क को नीचे गिराया जा सकता है। 2011 तक, यह काफी हद तक स्पष्ट था कि 2004 और 2011 के बीच उधार ऋण देने के लिए पीएसबी मुश्किल में थे । लेकिन सफाई केवल 2015 के मध्य में शुरू हुई जब आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर राजन ने संपत्ति की शुरुआत की बैंकों की समीक्षा की। उस समय तक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी कि इसे विनियामक नीति कहा जाता है और संयम दिखाया जाता है। यह कई पुनर्गठन योजनाओं के साथ आया, जिससे बैंकों को ऋण की अवधि बढ़ाने या ब्याज दर में कमी करने की अनुमति मिली। कुछ मामलों में, नए ऋण भी दिए गए ताकि कॉर्पोरेट पुराने ऋणों को चुका सकें जो कि होने वाले थे। यह सब बैंकों को खराब ऋणों की मान्यता को स्थगित करने में मदद करता है।

इसके पीछे विचार यह था कि बैंक नए ऋण देकर इससे बाहर बढ़ने का प्रबंधन करेंगे और अंततः बुरा ऋण समग्र ऋणों का बहुत छोटा हिस्सा बन जाएगा। बेशक, ऐसा नहीं हुआ। इसके लगने से, सड़क के नीचे खराब ऋणों को मारने की प्रथा इस समय के आसपास भी होने की संभावना है। पहले से ही वित्त मंत्रालय और RBI के बीच एक बार के पुनर्गठन की योजना के बारे में बहुत सी बातें चल रही हैं। निस्संदेह, जो वातावरण उभर कर आएगा, उसमें कई बैंक ताजा ऋण देना पसंद नहीं करेंगे, और व्यक्तिगत और कॉरपोरेट उधारी के रूप में भी बैकसीट लिया जाएगा। इसलिए, बैंक जमा पर ब्याज और कम हो जाएगा। यह आपके और मेरे आने वाले बैंकिंग संकट के लिए न्यूनतम लागत होगी। जैसा कि वे कहते हैं, अर्थशास्त्र में, मुफ्त भोजन नहीं है।

रूस का दावा

कोरोना वायरस के क्लिनिकल ट्रायल में 100 फीसदी सफल रही रूसी वैक्सीन

मास्को। एजेंसी

रूस ने कहा है कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में 100 फीसदी सफल रही है। इस वैक्सीन को रूस रक्षा मंत्रालय और गमलेया नैशनल सेंटर फॉर रिसर्च ने तैयार किया है। रूस ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल में जिन लोगों को यह कोरोना वैक्सीन लगाई गई, उन सभी में SARS-CoV-2 के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई गई।

यह ट्रायल 42 दिन पहले शुरू हुआ था। उस समय वॉलंटियर्स (वैज्ञानिक शोधकर्ता) को मास्को के बुरदेंको सैन्य अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। ये लोग सोमवार को दोबारा अस्पताल आए और उनकी सघन जांच की गई। इस दौरान पाया गया कि सभी लोगों में कोरोना वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हुई है। इस जांच परिणाम के बाद सरकार ने रूसी वैक्सीन की तारीफ की है।

रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा, 'समीक्षा के परिणामों से यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि वैक्सीन लगने की वजह से लोगों के अंदर मजबूत रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया विकसित हुई है।' रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि किसी भी वॉलंटिअर के अंदर कोई भी नकारात्मक साइड इफेक्ट या परेशानी नहीं आई। यह प्रयोगशाला अब बड़े पैमाने पर जनता में इस्तेमाल से पहले सरकार की स्वीकृति लेने जा रही है।

रूस ने दावा किया है कि वह कोरोना वायरस के खिलाफ जारी वैश्विक लड़ाई में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने में वह दूसरों से कई महीने आगे चल रहा है। बताया जा रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल में सफलता के बाद अब रूस वैक्सीन की प्रभावी क्षमता को परखने के लिए तीन व्यापक परीक्षण करने जा रहा है। रूस का इरादा है कि इस साल सितंबर तक कोरोना वैक्सीन को विकसित कर लिया जाए। साथ ही अक्टूबर महीने से देशभर में टीकाकरण शुरू कर दिया जाए।

कोरोना की एक और दवा बाजार में, जानिए कितनी है कीमत

नयी दिल्ली। एजेंसी

दवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ल्यूपिन ने बुधवार को कोविड- 19 के हल्के और कम गंभीर रोगियों के इलाज के लिए दवा फेविपिराविर को 'कोविहाल्ट' ब्रांड नाम के साथ बाजार में उतारा है। इसकी एक गोली का मूल्य 49 रुपये रखी गई है। ल्यूपिन ने शेयर बाजारों को भेजी नियामकीय जानकारी में कहा है कि फेविपिराविर को आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) से अनुमति मिल गई है। इसमें कहा गया है कि कोविहाल्ट में दवा की मात्रा को प्रशासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है।

कंपनी ने कहा कि यह दवा 200 मिलीग्राम की गोली के रूप में 10 गोलियों की स्ट्रिप के रूप में उपलब्ध होगी। प्रत्येक गोली का दाम 49 रुपये रखा गया है। ल्यूपिन के इंडिया रीजन फॉर्म्यूलेशंस (आईआरएफ) के प्रेजिडेंट राजीव सिब्बल ने कहा कि कंपनी को तपेदिक जैसे तेजी से फैलने वाले संक्रमण रोगों को व्यवस्थित करने के क्षेत्र में जो अनुभव है उसका लाभ वह उठा सकेगी। वह अपने मजबूत वितरण नेटवर्क और मैदानी क्षेत्र में काम करने वाले कार्यबल के बलबूते देशभर में कोविहाल्ट की पहुंच सुनिश्चित कर सकेगी।

सन फार्मा की गोली 35 रुपये में

इससे पहले सन फामास्युटिकल इंडस्ट्रीज ने भी फेविपिराविर को 'फ्लूगार्ड' ब्रांड नाम के तहत बाजार में उतारा है। उसने अपनी एक गोली की कीमत 35 रुपये रखी है। देश में कोरोना का मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से रोजाना करीब 50 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1908254 पहुंच चुकी है। इनमें से 1282215 मरीज रिकवर हो चुके हैं जबकि 39795 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के 586244 एक्टिव मामले हैं।

सरकार ने सभी तरह के वेंटिलेटर के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने मंगलवार को सभी तरह के वेंटिलेटर के निर्यात पर प्रतिबंध को हटा दिया, ताकि उन उत्पादों के विदेश व्यापार में तेजी लाई जा सके। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, "किसी भी तरह के कृत्रिम श्वसन तंत्र या ऑक्सीजन उपचार उपकरण या किसी अन्य श्वास उपकरण सहित सभी तरह के वेंटिलेटर निर्यात के लिए मुक्त हैं।"कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए घरेलू स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के मकसद से इन उत्पादों के निर्यात पर 24 मार्च को प्रतिबंध लगाया गया था।कोविड-19 पर गठित मंत्रियों के समूह ने एक अगस्त को इस बारे में विचार किया और भारत में बने वेंटिलेटर के निर्यात की अनुमति देने वाले स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमति जताई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कोविड-19 महामारी को काबू में करने के भारत के प्रयासों में उल्लेखनीय प्रगति और कम संख्या में वेंटिलेटर की जरूरत होने के कारण यह फैसला किया गया। यह बयान एक अगस्त को जारी किए गया था। बयान में कहा गया कि वेंटिलेटर की घरेलू विनिर्माण क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है और इस समय वेंटिलेटर के लिए 20 से अधिक घरेलू विनिर्माता हैं।

जनधन योजना के तहत बैंक खातों की संख्या 40 करोड़ के पार, मिलती हैं कई सुविधाएं

नई दिल्ली। एजेंसी

मोदी सरकार के वित्तीय समावेश कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। योजना की शुरुआत 6 साल पहले की गई थी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 40.05 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए हैं और इन खातों में जमा राशि 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवाओं के विभाग (डीएफएस) ने एक ट्वीट में कहा है कि दुनिया के सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी कार्यक्रम, पीएमजेडीवाई के तहत एक और अहम पड़ाव हासिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत खोले गए कुल खातों की संख्या 40 करोड़ के पार निकल गई है। वित्तीय समावेश के इस कार्यक्रम को इसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध।

जनधन (Jan Dhan) खाते में ओवरड्राफ्ट, रुपे कार्ड की सुविधा

जनधन खातों में यह सफलता योजना की छठी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले ही हासिल हुई है। योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। योजना का मकसद देश के तमाम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। पीएमजेडीवाई के तहत खोले जाने वाले जनधन खाते बुनियादी बचत बैंक खाते हैं। इनके साथ रुपे कार्ड और खाताधारक को ओवरड्राफ्ट देने की अतिरिक्त सुविधा दी जाती है। इस खाते में खाताधारक को खाते में हर समय न्यूनतम राशि बनाये रखने की आवश्यकता नहीं होती है।

दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर किया गया 2 लाख रुपए

योजना की सफलता के लिए सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद खोले जाने वाले ऐसे जनधन खातों के साथ दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया जो कि पहले 1 लाख रुपये रखी गई थी। इसके साथ ही खाते में ओवरड्राफ्ट सुविधा की सीमा को भी बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। सरकार ने योजना के तहत प्रत्येक घर से बैंक खाता खोलने के बजाय अपना ध्यान अब प्रत्येक वयस्क का बैंक खाता होने की तरफ कर दिया है।

महिला जनधन (Jan Dhan) खाते में 1,500 रुपए डाले गए

जनधन खाताधारकों में 50% से अधिक महिलाएं हैं और सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड-19 संकट में गरीबों को मदद देने के वास्ते तीन समान मासिक किस्तों में 1,500 रुपए उनके खाते में डाले हैं। सरकार ने 26 मार्च 2020 को जनधन खाताधारकों के खाते में अप्रैल से तीन महीने तक हर महीने 500 रुपए की सहायता राशि पहुंचाने की घोषणा की। पीएमजेडीवाई योजना का मकसद सभी की बैंकिंग तंत्र तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही समाज के कमजोर और निम्न आयवर्ग के हर वयस्क व्यक्ति का एक बुनियादी बचत बैंक खाता, जरूरत के मुताबिक कर्ज लेने की सुविधा तथा बीमा और पेंशन की सुविधा मुहैया कराना है। जनधन बैंक खातों के जरिये लोगों को मिलने वाले सरकारी लाभों को भी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डालने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को आगे बढ़ाने का बेहतर जरिया साबित हुआ है।

भारत ने चीन, जापान, तीन अन्य देशों से आयातित डिजिटल प्रिंन्टिंग प्लेट पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया

नयी दिल्ली। भारत ने चीन, जापान, कोरिया, ताइवान और वियतनाम से आयातित डिजिटल प्रिन्टिंग प्लेट पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। घरेलू विनिर्माताओं को इन देशों से होने वाले सस्ते आयात से बचाने के लिये यह कदम उठाया गया है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने मामले की जांच के बाद शुल्क लगाने की सिफारिश की। जांच में पाया गया कि इन देशों से डिजिटल प्रिन्टिंग प्लेट के आयात में निरपेक्ष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में कहा, "अधिसूचना के तहत डंपिंग रोधी शुल्क पांच साल के लिये प्रभावी होगा।" शुल्क 0.13 डॉलर प्रति वर्ग मीटर (एसक्यूएम) से 0.77 डॉलर प्रति वर्ग मीटर की दर से लगाया गया है। डीजीटीआर ने कहा कि इन देशों से भारत को प्लेट का निर्यात सामान्य मूल्य से नीचे पर किया जाता रहा है जिससे डंपिंग की स्थिति पैदा हुई और घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ। इन प्लेटों का आयात जांच अवधि (जुलाई 2018 से मार्च 2019) के दौरान बढ़कर 1.632 करोड़ एसक्यूएम रहा जो 2015-16 में 80 लाख एसक्यूएम था। इस उत्पाद का उपयोग छपाई उद्योग में आंकड़े को कागज या 'पॉली फिल्म' पर छवि के रूप में स्थानांतरित करने में किया जाता है। एक अलग अधिसूचना में राजस्व विभाग ने कहा कि उसने चीन ने आयातित एनिलाइन पर छह महीने के लिये अस्थायी तौर पर 150.80 प्रति टन तक की दर से डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है।

भारत में पाम खेती को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता: ओपीडीपीए

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत में आयल पॉम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है क्योंकि देश मौजूदा समय में खाद्य तेलों की जरुरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में आयात पर निर्भर है। तेल प्रसंस्करणकर्ताओं के निकाय ओपीडीपीए ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पाम तेल विकासकर्ता एवं प्रसंस्करणकर्ता संघ (ओपीडीपीए) ने कहा कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में पाम तेल के लिये खेती की बहुत बड़ी गुंजाइश है, अकेले अरुणाचल प्रदेश और असम में इसके तहत दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाने की क्षमता मौजूद है। ओपीडीपीए के अध्यक्ष संजय गोयनका ने एक बयान में कहा, "इस फसल को पूरे भारत में आवश्यक गति देने के लिए एक मजबूत और दीर्घकालिक नीति तंत्र की आवश्यकता है।" मौजूदा समय में, अपनी क्षमता के मुकाबले देश में पॉम की खेती बहुत ही नगण्य है। गोयनका ने कहा कि इस फसल ने आंध्र प्रदेश में किसानों के जीवन में बदलाव ला दिया है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसका अनुकरण किया जा सकता है। पाम की फसल एक काफी लाभकारी फसल है जिसमें अन्य वाणिज्यिक फसलों की तुलना में प्रति एकड़ निवेश पर सबसे अधिक लाभ की क्षमता है। इसने कहा कि इसके सदस्यों ने पहले ही एक जनाधार बना लिया है और फसल के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तर पूर्वी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

राजा दशरथ का महल अयोध्या

अयोध्या में रामकोट स्थित 'दशरथ महल' दशरथ जी का राजमहल जो जिसे आज एक सिद्ध पीठ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस स्थान पर श्री वैष्णव परम्परा की प्रसिद्ध पीठ एवं विन्दुगादी की सर्वोच्च पीठ भी स्थित है। इस पौराणिक महल का कालांतर में कई बार जीर्णोद्धार हुआ है। महाराज दशरथ के महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। राम विवाह, दीपावली, श्रावण मेला, चैत्र रामनवमी और कार्तिक मेला का यहां उत्साह के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ महल में राजा दशरथ अपने नाते-रिश्तेदारों के साथ रहते थे। यह स्थल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में तब्दील हो चुका है, जहां राम-सीता, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदित की प्रतिमाएं हैं। यह स्थल सैलानियों के लिए सुबह 8 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 से लेकर रात के 10 बजे तक खोला जाता है।

अयोध्या में हनुमान गढ़ी से नजर रखते हैं हनुमानजी इस रामकोट पर

अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित हनुमानगढ़ी सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान यहां एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। यही से श्रीराम भक्त हनुमान रामकोट पर नजर रखते हैं। रामजन्म भूमि अयोध्या में सबसे पवित्र जगहों में से एक है। रामजन्म भूमि वह जगह है जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और एक मंदिर भी बना था। हनुमानजी हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि पर नजर रखते हैं। दूसरी ओर वे रामकोट पर भी नजर रखते हैं। अयोध्या के रामकोट अर्थात अयोध्या नगरी का परकोटा। हनुमान टीले से संपूर्ण अयोध्या को देखा जा सकता है। शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट अयोध्या में पूजा का प्रमुख स्थान है। यहां भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। रामकोट के प्राचीन गढ़ की जगह है जो शहर के पश्चिमी भाग में एक ऊंची भूमि पर स्थित है। यह जगह भगवान राम के किले की एक जगह है जो प्राचीनकल में अस्तित्व में थी। यह वही स्थान है जहां भगवान राम को कोशल के राज्य और रिश्तेदारी से सम्मानित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि शहर को जैनियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, क्योंकि इस पवित्र शहर में पांचों थरथरकारों का जन्म हुआ था। यहां के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में हनुमान गढ़ी, कनक भवन, रामकोट गढ़, स्वर्ग द्वार, मनी पर्वत और सर्गीव पार्वत, नागेश्वरनाथ मंदिर आदि शामिल हैं। अयोध्या में स्मारक अच्छी तरह से बनाए गए हैं और अच्छे पर्यटन स्थलों के लिए बनाता है।

अयोध्या का दर्शनीय स्थल

त्रेता के ठाकुर

त्रेता के ठाकुर अर्थात त्रेतायुग के भगवान राम का वह स्थान जहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस यज्ञ स्थल पर एक भव्य मंदिर बना दिया गया है। त्रेता के ठाकुर अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह वही जगह है जहां पर श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस मंदिर में भगवान राम की मूर्तियों को रखा गया है जो प्राचीन समय में काले रेत के पत्थरों से उकेरी गई थीं। यह कलाकारी का बेहद अच्छा नमूना है। अगर आप अयोध्या की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आपको इस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए जरुर जाना चाहिए।

अयोध्या का वह स्थान जहां श्री राम करते थे अपने दांतों की सफाई

सप्तपुरियों में से एक सरयू तट पर बसी प्रभु श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या में राम के जीवन से जुड़े कई स्थान है एक ओर जहां उनकी पत्नी सीता का कनक भवन है तो दूसरी ओर उनके पिता का महल। उनके प्रिय हनुमान का हनुमानगढ़ी में स्थान है तो इसी तरह वह स्थान भी है जहां प्रभु राम अपने दांतों की सफाई करते थे। उस स्थान को दंत धावन कुंड या राम दतौन कहते हैं। हनुमानी गढ़ी क्षेत्र में ही दन्तधावन कुंड है जहां श्रीराम अपने भाइयों के साथ अपने दांतों की सफाई कर कुल्ला करते थे। इसे ही राम दतौन भी कहते हैं। इस कुंड में कई दुर्लभ प्रजाती के कछुए तैरते रहते हैं। अयोध्या में उत्सव के दौरान इस कुंड के आसपास लाइटिंग की जाती है और इसे सजाया जाता है। इसके आलावा यहां सीता कुंड, दशरथ कुंड, विभीषण कुंड है जो उनके निजी हुआ करते थे। इसके अलावा वशिष्ठ कुंड, लोमश गणेश कुंड, सूर्य कुंड, शत्रुघ्न कुंड और बृहस्पति कुंड भी है। ब्रह्मा कुंड जहां ब्रह्मा ने तप और यज्ञ किया था और जहां पर सिख गुरुनानकदेवी ने ध्यान किया था।

अयोध्या में सरयू तट का वह घाट जहां पर श्रीराम ने ली थी जल समाधि

सरयू नदी के तट पर बसी सप्त पुरियों में से एक अयोध्या नगरी प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि है। सरयू तट पर कई प्राचीन घाट हैं। हर एक घाट से जुड़ी पौराणिक कथाएं हैं। इसी तरह से एक घाट ऐसा हैं जहां श्रीराम ने सरयू में उतरकर जल समाधी ले ली थी। आओ जानते हैं उस घाट के बारे में। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्त द्वार घाट, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, पापमोचन घाट, लक्ष्मण घाट या सहस्त्रधारा घाट, ऋणमोचन घाट, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिल्याबाई घाट, धौरहरा घाट, नया घाट और जानकी घाट आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

1. गुप्त द्वार : इस गुप्तार घाट भी कहते हैं। इसी स्थान पर श्रीराम ने भरत और शत्रुघ्न की पत्नियों और अयोध्या के सभी नगरवासियों सहित जल समाधि लेकर साकेत धाम को गमन किया था। कहते हैं कि इस घाट पर नदी में डुबकी लगाने वाला कभी यमपुरी का दर्शन नहीं करता है और भगवान् के ही धाम को पहुंच जाता है। 19 वीं सदी में राजा दर्शन सिंह द्वारा इसका नवनिर्माण करवाया गया था। घाट पर राम जानकी मंदिर, पुराने चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर स्थित है, जिसके लोग दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर घाट के निकट मिलिट्री मंदिर, अंग्रेजी हुकूमत के दौर से सुव्यवस्थित कम्पनी गार्डन एवं राजकीय उद्यान भी है जहां शहरवासी परिवार के साथ छुट्टीयां मनाते हैं। बक्सर की युद्ध विजय के बाद तत्कालीन नबाब शुजा-उद-दौला द्वारा निर्मित एतिहासिक किला, गुप्तार घाट से चंद कदमों की दूरी पर स्थित है। यहां पर नौका विहार करने के आनंद ही कुछ और है। लंबे तट पर रेतीले मैदानों के इर्द-गिर्द हरियाली और एकदम शान्त वातावरण एवं सूर्यास्त की निराली छटा लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है।

सहस्त्रधारा घाट : स्कन्द पुराण के अनुसार यहां सहस्त्रधारा घाट पर श्रीराम से पूर्व ही लक्ष्मणजी ने अपना शरीर छोड़ा और शेषनाग के रूप में दिखाई दिए थे। उसके बाद वो अपने पाताल लोक चले गए और उनके शरीर के स्थान पर वहां शेषावतार मंदिर बनाया गया। मान्यता है कि इस घाट पर पहुंचकर झूठ नहीं बोला जाता अन्यथा उस पर मृत्यु मंडराने लगती है। नाग पंचमी के दिन यहां बहुत बड़ा मेला लगता है इस दिन इस मंदिर में पूजा का विशेष महत्त्व है।

कार कंपनियों के कारखानों में वापस लौटी रौनक, बाजार में बढ़ी गाड़ियों की खरीदारी

कोरोना वायरस महामारी से हुए नुकसान से अब ऑटो इंडस्ट्री तेजी से उबरने लगी है। जून महीने में देशभर में 9 लाख से ज्यादा वाहनों की बिक्री हुई थी। वहीं, अब जुलाई में वाहनों की बिक्री में पिछले महीने के मुकाबले और भी तेजी आई है। इस कड़ी में अब वाहन कंपनियां अपने वाहनों के प्रोडक्शन को बढ़ाने लगी हैं। बात करें पैसेंजर वाहन सेगमेंट की तो लॉकडाउन के बाद बढ़ती मांग को देखते हुए कार कंपनियां अपने कारखानों में गाड़ियों के प्रोडक्शन की रफ्तार बढ़ा रही हैं। त्योहारी सीजन में अब महज कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं, ऐसे में मारुति सुजुकी और ह्यूंदै इंडिया भारत में अपने वाहनों के प्रोडक्शन को बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही हैं।

मारुति सुजुकी बढ़ाएगी कारों की संख्या

अक्टूबर महीने में मारुति अपने कारखानों में 1,60,000-1,70,000 तक कारें बनाएगी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने इस महीने अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए आक्रमक रणनीति बनाई है। कंपनी ने अपने सप्लायर्स और कर्मचारियों को अक्टूबर महीने में ज्यादा काम (अतिरिक्त दिन) करने को कहा है।

ह्यूंदै भी बढ़ाएगी अपनी रफ्तार

अक्टूबर महीने में मारुति की तरह ही ह्यूंदै भी अपने वाहनों के प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। ह्यूंदै अपने कारखानों में 58,000-60,000 तक कारें बनाएगी। कंपनी को उम्मीद है कि इस त्योहारी सीजन उसके Creata और Venue को भारतीय बाजार में ग्राहकों की तरफ से ज्यादा खरीदा जाएगा।

भारतीय बाजार में बढ़ाएंगी अपना दबदबा

मारुति सुजुकी और ह्यूंदै की बिक्री को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो भारत में बिकने वाली सभी कारों का 60 फीसदी हिस्सा इन दो कंपनियों के पास है। यानी अगर देश में 100 कारें बिकती हैं, तो उनमें 68 कारें मारुति और ह्यूंदै की होती हैं।

दोनों ही कंपनियों ने वित्तवर्ष 2017-18 और वित्तवर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में अपने वाहनों को बनाने की संख्या बढ़ा दी थी, लेकिन इसके बाद भारत में वाहनों की बिक्री घटने लगी जिसका असर इनके प्रोडक्शन पर भी पड़ने लगा। हालांकि, बिक्री घटने के पीछे कई कारण थे जिनमें भारत समेत अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आर्थिक सुस्ती, कच्चे माल और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ नए सुरक्षा नियम और बीएस6 नॉर्म्स शामिल थे।

जुलाई में क्या है हाल?

जुलाई महीने में मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में 1 लाख से ज्यादा कारों की बिक्री की है। जबकि, जून महीने में इसके 51,274 और मई महीने में इसके 13,865 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। वहीं, भारतीय बाजार में ह्यूंदै की जुलाई महीने में 38,200 कारों की बिक्री हुई। कंपनी ने जून में 21,320 और मई में 5,500 यूनिट्स की बिक्री की थी।

त्योहारी सीजन में एसयूवी 'अर्बन क्रूजर' उतारने की तैयारी में टोयोटा

नयी दिल्ली। एजेंसी

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) देश के कॉम्पैक्ट एसयूवी खंड में उतरने जा रही है। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि वह आगामी त्योहारी सीजन में 'अर्बन क्रूजर' के साथ इस बाजार में उतरेगी। चार मीटर से कम का यह मॉडल मारुति सुजुकी इंडिया की विटारा ब्रेजा पर आधारित है। अर्बन क्रूजर के जरिये कंपनी ऐसे खंड में चुनौती पेश करेगी, जिसमें चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल के बावजूद बिक्री का आंकड़ा बेहतर है। विटारा ब्रेजा के अलावा यह मॉडल हुंदै की वेन्यू, टाटा नेक्सन तथा किया मोटर्स और निसान के आगामी मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। टीकेएम ने कहा कि अर्बन क्रूजर उन उपभोक्ताओं के लिए होगी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी से कुछ अधिक चाहते हैं। कंपनी ने कहा कि वह कॉम्पैक्ट एसयूवी त्योहारी सीजन में पेश करेगी। कंपनी का इरादा भारत में कॉम्पैक्ट एसवीयू की बढ़ती मांग का लाभ उठाना है। टीकेएम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (बिक्री एवं सेवा) नवीन सोनी ने कहा, ''ग्राहक-पहले के रुख के साथ टीकेएम नए उत्पादों के साथ ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा करने को प्रतिबद्ध हैं। टोयोटा अर्बन क्रूजर इसी दिशा में हमारा एक और प्रयास है।''

पांच साल में तीसरा सबसे बड़ा खुदरा वाहन ब्रांड बना मारुति का नेक्सा

मुंबई। एजेंसी

देश की सबसे बड़ी वाहन विनिर्माता कंपनी मारुति सुजकी का प्रीमियम खुदरा ब्रांड नेक्सा अपनी शुरुआत के महज पांच साल में ही देश का तीसरा सबसे बड़ा खुदरा वाहन ब्रांड बन गया है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह दावा किया है।मारुति सुजुकी ने जुलाई 2015 में नेक्सा की शुरुआत की थी। अभी नेक्सा की कार बाजार में 11 प्रतिशत से कुछ अधिक हिस्सेदारी है तथा मारुति की सालाना बिक्री में यह 20 प्रतिशत से अधिक योगदान देता है। नेक्सा के तहत मारुति के पांच प्रीमियम मॉडल की बिक्री होती है। मारुति सुजुकी के कार्यकारी निदेशक (बिक्री एवं विपणन) शशांक श्रीवास्तव ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''नेक्सा किसी कार निर्माता कंपनी की महज बिक्री से आगे बढ़कर खुदरा अनुभव का नया स्वरूप तैयार करने का पहला प्रयास है। नेक्सा ने इस जुलाई में अपने पांस साल पूरे किये हैं और इसने अनोखे उपभोक्ता अनुभव के साथ अब तक 11 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवाएं दी है।'' नेक्सा के तहत सबसे पहले एस-क्रॉस की बिक्री शुरू की गयी थी। बाद में अक्टूबर 2016 में नेक्सा के साथ बलेनो को जोड़ा गया। इसके बाद जनवरी 2017 में हैचबैक इग्निस, अप्रैल 2017 में सेडान सियाज और अगस्त 2019 में बहुद्देश्यीय वाहन (एमपीवी) एक्सएल6 को नेक्सा के मंच पर उतारा गया। अभी देश भर के 200 शहरों में 370 नेक्सा शोरूम हैं। हालांकि, कोरोना वायरस महामारी का वाहन उद्योग पर पड़े असर को लेकर श्रीवास्तव फिलहाल इसके विस्तार को लेकर सतर्क हैं। उन्होंने कहा, ''आज, नेक्सा तीसरा सबसे बड़ा खुदरा वाहन चैनल है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 10-11 प्रतिशत है। वर्तमान में, नेक्सा हमारी कुल बिक्री का 20 प्रतिशत योगदान देता है। नेक्सा के साथ, हम आधुनिक शहरी उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में सक्षम हैं।'' उन्होंने कहा कि नेक्सा ने सितंबर 2019 में महज चार साल दो महीने में 10 लाख ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा। इसके बाद जुलाई 2020 तक इसने एक लाख और उपभोक्ताओं को अपने साथ जोड़ ग्राहकों की कुल संख्या को 11 लाख कर लिया।

अब किसानों से आस, भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर!

नई दिल्ली। एजेंसी

चीन से शुरू होकर दुनिया भर में फैलने वाला कोरोना वायरस महामारी के चपेट हमारा देश भारत भी बुरी तरह फंस गया। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इसको पटरी पर लाने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था लेकिन अभी तक बेहतर प्रदर्शन नजर नहीं आ रहा है। हालांकि वित्त मंत्रालय की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अर्थव्यवस्था को उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उम्मीद है किसानों की मेहनत रंग लाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर मानसून की संभावना है। आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से जारी जुलाई की आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल के संकट के बाद भारत अब पुनरोद्धार की राह पर है। इसमें सरकार और केंद्रीय बैंक की पॉलिसियों से समर्थन मिला है।

अर्थव्यवस्था का बुरा समय बीत गया?

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अनलॉक के चरण में हैं। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था का बुरा समय बीत गया है। हालांकि, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और विभिन्न राज्यों में बारी-बारी से लग रहे लॉकडाउन से खतरा कायम है। रिपोर्ट कहती है कि कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी और इसकी वजह से राज्यों द्वारा कुछ-कुछ दिनों लिए लगाए जा रहे लॉकडाउन से सुधार की संभावनाएं कमजोर पड़ रही हैं। ऐसे में इसकी निरंतर निगरानी करने की जरूरत है।

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में एग्रीकल्चर सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका

रिपोर्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर भरोसा जताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के झटकों से उबरने में एग्रीकल्चर सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन से जल्दी और सही समय पर छूट दी गई, जिससे रबी फसलों की कटाई समय पर हो सकी। साथ ही खरीफ फसलों की बुवाई भी की जा सकी।

एग्रीकल्चर सेक्टर नियंत्रण मुक्त हुआ

रिपोर्ट में हालिया एग्रीकल्चर सेक्टर के सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इससे एग्रीकल्चर सेक्टर नियंत्रण मुक्त हुआ है। साथ ही इनसे किसान सशक्त हुए हैं और वे भारत के विकास की कहानी का एक बड़ा और अधिक स्थिर भागीदार बन सके हैं।

गेहूं की रिकॉर्ड खरीद से किसानों को मिले 75,000 करोड़ रुपए

रिपोर्ट कहती है कि गेहूं की रिकॉर्ड खरीद से किसानों के हाथों में 75,000 करोड़ रुपए गए हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में निजी उपभोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर, 2019 से बिजनेस का रुख एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर हुआ है जिससे ग्रामीण मांग बढ़ाने में मदद मिली है। इससे मार्च से जून, 2020 से ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य महंगाई दर बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन (IIP) की गतिविधियों और 08 बुनियादी उद्योगों के प्रोडक्शन में गिरावट अप्रैल की तुलना में मई में कम हुई है। इसी तरह जून में भारत का मैन्युफैक्चरिंग PIM 47.2 पर पहुंच गया। मई में यह 30.8 पर था। सेवा PIM मई के 12.6 से जून में 33.7 पर पहुंच गया।

रेपो रेट में होगी कटौती! मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू

मुंबई। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने तथा उद्योग जगत की ऋण पुनर्गठन की बढ़ती मांग के बीच द्वैमासिक मौद्रिक नीति पर मंगलवार को तीन दिवसीय चर्चा शुरू कर दी। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति 6 अगस्त को बैठक के नतीजों की घोषणा करने वाली है। यह एमपीसी की 24वीं बैठक है। रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी तथा इसकी रोकथाम के लिये लागू लॉकडाउन के असर को सीमित करने के लिये पिछले कुछ समय से लगातार सक्रियता से कदम उठा रहा है। तेजी से बदलती वृहद आर्थिक परिस्थिति तथा वृद्धि के बिगड़ते परिदृश्य के कारण रिजर्व बैंक की दर निर्धारण समिति को पहले मार्च में और फिर मई में समय से पहले ही बैठक करने की जरूरत पड़ी थी। मार्च और मई 2020 के अंत में हुई बैठकों में रेपो दर में कुल 1.15 प्रतिशत की कटौती की जा चुकी है। इससे पहले फरवरी 2019 से अब तक रेपो दर में 2.50 प्रतिशत तक कटौती की जा चुकी है। हालांकि, विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर एकराय नहीं है कि समिति इस सप्ताह की बैठक में नीतिगत दर में कटौती करेगी या नहीं। कई विशेषज्ञों की राय है कि मौजूदा स्थिति में कर्ज का एक बार पुनर्गठन अधिक आवश्यक है।

रेपो रेट में कटौती होगी या नहीं

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक शोध रिपोर्ट इकोरैप में कहा गया कि बैंकों ने भी नये कर्ज पर 0.72 प्रतिशत तक ब्याज को सस्ता किया है। कुछ बड़े बैंकों ने तो 0.85 प्रतिशत तक का लाभ ग्राहकों को दिया है। यह संभवतः भारतीय इतिहास में सबसे तेजी से राहत दिये जाने का मामला है। एसबीआई ने रेपो से जुड़े कर्ज की ब्याज दरों को 1.15 प्रतिशत सस्ता किया है।उल्लेखनीय है कि मांस, मछली, खाद्यान्न और दालों की अधिक कीमतों के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जून में 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गयी। हालांकि, रिजर्व बैंक को सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत (दो प्रतिशत ऊपर या नीचे) के दायरे में रखने का लक्ष्य दिया है। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति निर्धारित करते समय मुख्य रूप से सीपीआई पर गौर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एमपीसी तेजी से बदलते व्यापक आर्थिक माहौल के मद्देनजर मौद्रिक नीति पर उदार रुख बरकरार रखेगी।

फाइनेंसियल कमर्शियल क्रेडिट नोट जीएसटी क्यो नही लगेगा, समझिए

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

टारगेट सेल को प्राप्त करने पर सामान्यता वर्ष खत्म होने के बाद सभी कंपिनयां अपने डीलर को डिस्काउंट के रूप में पैसा देती है। इस पर जीएसटी दोबारा नही लगना चाहिए। इस परिपेक्ष्य में इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ट्रांसेक्शन वैल्यू से संबधित धारा 15(2)(बी) को समझनें को समझना पडेगा जिसमें कहा गया है कि यदि कोई माल खरीदने वाला जैसे भाडे का भुगतान करता है जो कि विक्रेता को करना था और इस भाडे को विक्रेता ने बिल में ट्रांसेक्शन वैल्यू ले लिया है और भाडे सहित विभाग को सप्लायर ने टैक्स दे दिया है तो ट्रांसजेक्शन वेल्यू भाडे सहित मानी जाएगी। मतलब भाडे का पेमेंट सप्लायर को ही करना था लेकिन किसी परिस्थितिवश उस वक्त सप्लायर नही कर पाया तो खरीददार ने सप्लायर के बिहाफ पर भुगतान कर दिया। यहां ट्राजेक्शन वैल्यू भाडे के अमाउंट से कम नही मानी जाएगी। मतलब जो विक्रेता के बिहाफ पर क्रेता ने कर भुगतान करते कर दी। यहां भाडे का ट्रीटमेंट पहले ही बिल में हो चुका है और उस पर विक्रेता ने टैक्स भी भर दिया है तो यह भाडे से संबधित दोनो के बीच ट्रांसेक्शन फाइनेंसियल/ नगद ट्रांसेक्शन मात्र है न कि कोई नवीन सप्लाइ से संबधित ट्रांजेक्शन है। मतलब सोर्स ऑफ क्रेडिट फंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में से ही आ रही है जिस पर पहले ही टैक्स दिया जा चुका है। मतलब यह ट्रांजेक्शन उपरोक्त सप्लाई से ही संबंधित है। इसी कारण तो क्रेडिट दी गई है। यह कोई अलग से सर्विस डीलर ने नही दी है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में टारगेट सेल पर डिस्काउंट क्यो दिया जाता है क्योकिं ज्यादा से ज्यादा माल डीलर बेचें। डीलर उरोक्त मिलने वाले डिस्काउंट को बेचते वक्त फाइनल ग्राहक को पास ऑन कर देता है। उपरोक्त उदहारण को इसमें फिट करके देखते है तो माना जाएगा की होलसेलर ने डीलर को अंडरसटेंडीग दी है की आप भाव कम कर के माल बेचो मै यह भाव कम जितनी राशी आपको डिस्काउंट के रूप में बाद में इक्ट्ठी दे दूंगा और वह इक्ट्ठी राशि को डीलर को फाइनेंसियल क्रेडिट नोट के माध्यम से दे देता है।

इसका मतलब जब खरीददार और बेचवाल दोनो औरिजनिल वेल्यू और आईटीसी को डिस्टर्ब नही कर सकते है क्योकि धारा 15(3)(बी)(।।) के अनुसार क्रेता क्रेडिट नही ले पाऐगा इस प्रकार विक्रेता कंडीशन पूरी नही कर पाता है ना विक्रेता को अपनी ओरिजनल सेल वैल्यू को कम करने की परमिशन जीएसटी कानून देता है। धारा 34 के अनुसार भी विक्रेता क्रेडिट नोट सिर्फ 4 कंडीशन में ही इशू किया जा सकता है। धारा 34 (2) का प्रोविजन कहता है कि यदि टैक्स किसी और से वसूल कर लिया है। मतलब टैक्स का भार किसी और को विक्रय के माध्यम से पास ऑन कर दिया है, तो भी सप्लायर क्रेडिट नोट जीएसटी कानून के हिसाब से इशू नही कर सकता है। मतलब जीएसटी कानून में इस ट्रांजेक्शन की परमिशन ही नही होने से इसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मानकर पूरा किया जा रहा है। जैसे किसी ने उधार लिया और दिया। इस पर विभाग को टैक्स का घाटा कही भी नही है। उपरोक्त ट्रांसेक्शन मात्र फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है विभाग में भी फार्म 9सी में कॉलम 5एफ दिया है। मतलब विभाग भी फाइनेंशियल क्रेडिट को स्वीकार कर चुका है। सकुर्लर 92 के अनुसार भी फाइनेंशियल क्रेडिट नोट को स्वीकार किया गया है। बैंगलौर एडवांस जीएसटी ऑथरिटी ने भी क्वावलिटी मोबाइक के केस में भी पॉजिटीव निर्णय दिया है।

सोने के भाव ने तोड़े सारे रिकॉर्ड 4490 रुपये उछली चांदी

नई दिल्ली। एजेंसी

बुधवार को सोना अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 55000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है। वहीं चांदी 70000 रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गई है। देशभर के सर्राफा बाजारों सोना 1197 रुपये की बड़ी छलांग लगाते हुए 55201 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं 4490 रुपये प्रति किलो की ऊंची छलांग लगाती हुई चांदी 69225 रुपये पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट (ibjarates.com) के मुताबिक 5 अगस्त 2020 को देशभर के सर्राफा बाजारों सोने-चांदी के हाजिर भाव इस प्रकार रहे...

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन दिल्ली के मीडिया प्रभारी राजेश खोसला के मुताबिक ग्रैं देशभर के 14 सेंटरों से सोने-चांदी का करेंट रेट लेकर इसका औसत मूल्य बताता है। खोसला कहते हैं कि सोने-चांदी का करेंट रेट या यूं कहें हाजिर भाव अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकते हैं पर इनकी कीमतों में मामूली अंतर होता है। बता दें हाजिर बाजार में चांदी का भाव 2011 में 77,000 रुपये प्रति किलो तक उछला था। सोने का भाव 16 मार्च 2020 को 38,400 रुपये प्रति 10 ग्राम था जिसके बाद सोने में करीब 40 फीसदी की तेजी आई है।

धातु	5 अगस्त का रेट (रुपये/10 ग्राम)	4 अगस्त का रेट (रुपये/10 ग्राम)	रेट में बदलाव (रुपये/10 ग्राम)
Gold 999 (24 कैरेट)	55201	54004	1197
Gold 995 (23 कैरेट)	54980	53788	1192
Gold 916 (22 कैरेट)	50564	49468	1096
Gold 750 (18 कैरेट)	41401	40503	898
Gold 585 (14 कैरेट)	32293	31592	701
Silver 999	69225 Rs/Kg	64735 Rs/Kg	4490 Rs/Kg

क्यों बढ़ रहे सोने-चांदी के भाव

केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इससे शेयर बाजारों में जहां अनिश्चितता का माहौल है वहीं रियल एस्टेट भी पस्त पड़ा है। इस दौर निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित सोना ही नजर आ रहा है। निवेशकों का रुझान गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और बॉन्ड की तरफ बढ़ा है। यही वजह है कि सोने के रेट बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कोरोनावायरस संक्रमण के कारण खनन कार्य प्रभावित होने और आपूर्ति बाधित होने से चांदी की कीमतों में ज्यादा तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा चीन और अमेरिका के बीच व्यापार, व्यापार सहित कई मोर्चों पर तनाव बढ़ गया है। कोरोना वायरस से निपटने और चीन द्वारा हांगकांग के लिए एक सख्त नया सुरक्षा कानून थोपने की वजह से अमेरिका और चीन में एक नए शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है।

सोना और चांदी अपने शीर्ष तक पहुंचे

इस साल कीमतें 30 प्रतिशत अधिक

इंदौर। सराफा व्यवसायी संतोष वाधवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोने ने भारतीय बाजारों में अपना रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन आज भी जारी रखा है। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.2 फीसदी ऊपर 53,865 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी की बात करें, तो एमसीएक्स पर चांदी वायदा भी 0.18 फीसदी बढ़कर 65,865 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। संतोष वाधवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले सत्र में, सोने की कीमतें 0.5 फीसदी यानी 267 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी थीं, जबकि चांदी 1.2 फीसदी यानी 800 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी थी। पिछले सत्र में सोना 53,845 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वैश्विक बाजारों में, हाजिर सोना 1,976.36 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा। बढ़ते कोरोना वायरस मामलों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर चिंताओं से अमेरिकी डॉलर में दबाव डला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को लेकर एक चेतावनी जारी की है, जिसमें संगठन का कहना है कि कोरोना वायरस शायद लंबे समय के लिए रह सकता है।

वैश्विक बाजारों में सोने और चांदी की कीमतें इस साल 30 फीसदी ऊपर हैं, जिन्हें केंद्रीय बैंकों के प्रोत्साहन उपायों और कम ब्याज दर द्वारा समर्थित मिला। गोल्ड ईटीएफ में इस साल जोरदार उछाल देखने को मिला है क्योंकि पीली धातु को मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव और मुद्रा के खराब होने की आशंका के रूप में देखा जा रहा है।

संतोष वाधवानी, सराफा व्यवसायी

बैंकों ने ऋण गारंटी योजना के तहत एमएसएमई के लिये 1.38 लाख करोड़ रुपये के कर्ज मंजूर किए

नयी दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि बैंकों ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत लगभग 1,37,586 करोड़ रुपये के कर्ज मंजूर किये हैं। कोविड-19 महामारी के चलते आई आर्थिक मंदी के दौरान एमएसएमई क्षेत्र की मदद के लिए सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को तीन अगस्त तक 92,090.24 करोड़ रुपये का कर्ज वितरित भी किया जा चुका है। यह योजना सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए घोषित 20.97 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एक अहम हिस्सा है।वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा, "तीन अगस्त 2020 तक, 100 प्रतिशत आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों द्वारा कुल 1,37,586.54 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है, जिसमें से 92,090.24 करोड़ रुपये वितरित भी किये जा चुके हैं।"उन्होंने कहा कि इस आपात रिण सुविधा गारंटी योजना के तहत तीन अगस्त तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि 72,820.26 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 52,013.73 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों ने तीन अगस्त तक 64,766 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी गई जिसमें से 40,076 करोड़ रुपये की राशि वितरित कर दी गई। इससे पहले सरकार ने बीते शनिवार को इस योजना के दायरे को बढ़ाते हुए इसके दायरे में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए चिकित्सकों, वकीलों और चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे पेशेवरों को दिए व्यक्तिगत ऋणों को इसमें शामिल किया है। योजना के तहत अब 250 करोड़ रुपये कारोबार करने वाली कंपनियां भी आयेंगी। पहले इसमें अधिकतम 100 करोड़ रुपये तक कारोबार करने वाली कंपनियों को ही यह सुविधा देने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही योजना के तहत वित्तपोषण की राशि को दुगुना कर 10 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना में (ईसीएलजीएस) में बदलाव श्रमिक संगठनों की मांगों और जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई एमएसएमई की नई परिभाषा के आधार पर किया गया। कर्ज मंजूर करने वाले बैंकों में स्टेट बेंक सबसे आगे रहा है। एसबीआई ने 21,121 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया है जिसमें से 16,047 करोड़ रुपये का वितरण कर दिया गया है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने 9,809 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है और 6,351 करोड़ रुपये वितरित किये हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिये 9.25 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर तीन लाख करोड़ रुपये तक का गारंटी मुक्त कर्ज देने की इस योजना को मंजूरी दी थी।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।